

संसद में दार्ढी नेताओं की संख्या बढ़ना चिन्ताजनक

ऐसा पहली बार हुआ कि नीट-यूजी परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रैंक हासिल की। ऑल इंडिया स्टर पर प्रथम रैंक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है। इसलिए सदैव गहरा गया है। यह सदैव गहरात जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं धाँधली का जरिया बन गई हैं और यह सब कुछ प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। अनेक राज्यों में ऐप्रल लोक की बढ़ती घटनाओं से यह शक बनाना शुरू हुआ। अब देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एप्लिजिभिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट-यूजी) को लेकर खड़े हुए विवाद से यह और गहरा गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सचालों के घेरे में है। शक को इससे भी बल मिला कि जिस राज लोकसभा चुनाव की मतगणना में सारे देश का ध्यान था, एनटीए ने उसी रोज इमहान के नीतीजों को जारी करने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हुआ कि इस परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रैंक हासिल की। ऑल इंडिया स्टर पर प्रथम रैंक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है। एनटीए ने सफाई दी है कि आयोजन परीक्षा, रजिस्ट्रेशन में बढ़ोत्तरी, दो सही उत्तरों वाला एक प्रश्न और परीक्षा के समय में नुकसान की भरपूरी के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाना ऐसे करान हैं, जिनमें छात्रों को उच्च अंक लाने में सहायता मिली। मगर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के एक बड़े हिस्से को यह स्पष्टीकरण मंजूर नहीं है। वे परीक्षा रद कर इसे दोबारा करने की मांग कर रहे हैं। एनटीए का कहना है कि 1, 500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क की समीक्षा करने के लिए एक बार सदस्यों की कमेटी गठित की गई है, जो एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मगर सदैव इतना गहरा है कि ऐसे स्पष्टीकरण से छात्रों एवं समाज के एक बड़े हिस्से को संतुष्ट करने में सफलता नहीं मिली है। आरोग है कि ऐप्रल लोक किया गया। यह मुद्दा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सबवित जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने उठाया। उसने मामले की सीधी आई जांच और दोबारा परीक्षा करने को कहा है। जो हालात हैं, उनके बीच इन मामों को ठुकराना मुश्किल मालूम पड़ता है। अगर ऐसा कर भी दिया गया, तो यह परीक्षा की शुचिता पर सदैव जारी रखने की कीमत पर ही होगा।

खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना—हर नागरिक के माथे पर चिंता की लकीर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुद्धिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलाओं का विश्लेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफर्म्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात ख्याकार की थी, वहीं अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी हैरटी है। आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं।



लालत गग लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

१

मृत्यु तक राजनीति का बुखार हुआ है, मर्मिंटल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियाँ हैं वहीं चिन्ताजनक, विचलित एवं परेशान करने वाली स्थितियाँ भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपाराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपाराधिक छवि वाले या किसी आपाराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना हर नागरिक के माथे पर चिंता की लंकीर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतात्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दगदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विशेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट द्वारा यह प्रतीकान्वित हुआ है।

2021 के अंत तक, 543 सांसदों में जहाँ 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विश्वद्वारा आपाराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी, वहाँ अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपाराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है।

आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को आपाराधिक मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में आपाराधी तत्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं। अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता आम चुनाव में कहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को बोट दें ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं आपाराधी तत्वों को जिम्मेदारी के पद देकर कैसे सुशासन एवं ईमानदार व्यवस्था स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरें उतरेंगे? कैसे संसद में दायियों के पहुंचने के लिये द्वार बंद होंगे?

देशभर, युक्ति का बुखार लगा रहा है एवं अपराध मुक्त राजनीति को संदेश प्राथमिकता दी लेकिन चुनाव जीतने के रण में वे भी अपाराधी राजनेताओं को प्रश्न देते हुए दिखे हैं।

सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सबाल है कि देश के लिये नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपाराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या होगा हमारे समाज व व्यवस्था का भविष्य? क्यों तामां अदर्शों की बात करने वाले और दूसरे दलों के नेताओं की कारगुजारियों पर सावल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वरचर्च से मुक्त कराने की ईमानदार पहल नहीं करते? क्यों सभी राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में शुचिता एवं पवित्रता के लिये सहमति नहीं बनाते? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई वर्षों में दायियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ ही बड़ा सकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन-केन-प्रकारेंग करोड़पति बने नेताओं का वरचर्च बढ़ता ही जा रहा है। इस बार संसद में चुनकर आए सांसदों में 504 करोड़पति हैं। ऐसे द्वारा उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कर्माई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विड्जन्न एवं विसंगति बनते जा रहे हैं। बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ होता है। यह कैसी विवशता है राजनीतिक दलों की? अवसर राजनीति को अपराध मुक्त करने के दावे की हकीकत तब समाने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का

महाराज आराशवराज पर भरोसे का मतलब

केंद्रीय हिन्दू

चौहान आर पूर्व कद्रिय मत्राय ज्यातरादित्य साध्या को शामल करने के पीछे क्या बजह ये जनने में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। भाजपा के इन दो हासों की जोड़ी 2018 के विधान सभा चुनाव में आमने-सामने थी। तब महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और चौहान मप्र के मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में भाजपा ने माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज का नारा दिया था और कांग्रेस की ओर से माफ करो शिवराज, हमारे नेता महाराज का नारा उठला और कामयाब भी हुआ था। शिवराज सत्ताचुत हो गए थे, लेकिन महाराज अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे।

मप्र की इस जोड़ी ने ही 2020 में फिर कमाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बायावत कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री

कमलनाथ को पदच्युत कराकर अपने अपमान का बदला लिया और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा दी थी। 2020 से ही ये जोड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नजरों में चढ़ी हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस जोड़ी ने हाइटोड मेहनत कर मग्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनवाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो 2020 के करतब के लिए पुरस्कार के रूप में राज्य सभा की सदस्यता और केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान मिल गया था, किन्तु शिवराज सिंह को कोई इनाम-इकराम नहीं मिला था। उलटे उनके स्थान पर मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर चौहान को अपमानित जरूर किया गया था भाजपा की ओर से। शिवराज सिंह मंजे हुए खिलाड़ी निकले। उन्होंने अपमान का कड़वा घृणा कर बिना ना-नुकुर के पीछे लिया। नतीजा ये हुआ कि 2024 के आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चौहान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गयी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मंत्री बनना ही था क्योंकि वे प्रधानमंत्री के गांव-गौड़े के नाते दामाद लगते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उनका योग्यता और मौन साधना की वजह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक समय उनका नाम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी सुर्खियों में आया, लेकिन वे शायद अभी इस लायक नहीं बन पाए हैं।

प्रधानमंत्री ने केंद्र में बैशाखी सरकार का गठन करने के फौरन बाद

A close-up photograph of a woman with dark, wavy hair. She is looking down intently at a small, light-colored object she is holding in her hands. The background is blurred, showing what appears to be a garden or outdoor setting.

यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है। इन्हीं में से एक है

प्रश्नपत्र लाभ हान का समर्थन। शयद हा काइ एसा राज्य हा, जहा न किसा न किसा प्रतीत्यागा वा नियामत पराक्रमा का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सुर्खियों में न रहता हो। प्रश्नपत्र लीक होने की निरंतर घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की वारस्तविकता को कमजोर करती हैं और छात्रों के लिए काफी तनाव का कारण बनती हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, सख्त कानूनी उपाय और प्रभावित छात्रों के लिए व्यापक समर्थन शामिल है। इन उपायों को लागू करके, हम परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल कर सकते हैं और सभी छात्रों के लिए एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो परीक्षार्थियों के साथ परिजनों के भी सपने भी चकनाचूर होते हैं। ऐसी घटनाओं से एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र एवं समाज बनने-बनाने का हमारा सामूहिक स्वनन और मनोबल टूटा है। इससे युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं निराशा की स्थायी भावना घर करती है, शासन का प्रभाव कम होता है और व्यवस्था से आमजन का मोहब्बत गहता है। नौजवानों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल उच्चल भविष्य का, अपितु कई बार अस्तित्व का भी प्रश्न बन जाती हैं। इसके साथ ही सरकार की विश्वसनीयता संकट में पड़ती है। प्रश्नपत्र लीक करवाने के मामले में कई बार बड़े-बड़े कोरिंग केंद्रों एवं संचालकों की भी सालिसता पाई जाती है।



प्रयका सारम लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

३

दुर्दार असल तोमर यानि ग्वालियर के मुना भैया, मैन सिंह साबित हुए थे। वे न किसानों को मन पाए और न किसान यूनियनों को। उन्हें किसान संगठनों से संवाद स्थापित करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। उलटे सरकार के माथे पर 700 किसानों की हत्या का दाग और लग गया था। विवादास्पद कानून वापस लेने पड़े थे सो अलग। देश के किसान अभी भी आदेलित है। किसान आदेलन किसी भी समय भड़क सकता है। किसान आदेलन का खमियाजा भाजपा ने आम चुनावों में भी उठाया। ऐसे में बाचाल, मिलनसार और किसानों से सीधा रिश्ता कायम करने में समर्थ शिवराज सिंह चौहान को चुना गया। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी मंदसौर गोलीकाड़ का दाग लगा हुआ है। बहरहाल अब शिवराज सिंह को आपने आपको एक बार फिर प्रमाणित करना है। उनके पास एक मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल से जयादा समय का अनुभव है, जो प्रधायमंत्री जी के अनुभव से भी कहीं ज्यादा है। अब अइये महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिध्या की बात करते हैं। सिध्या के डीएपर्स में संघ, भाजपा और कांग्रेस के गुण समाहित हैं। सिध्या की दादी राजमाता विजयराजे सिध्या पहले कांग्रेसी, फिर जनसंघी और अंत में भाजपा में रहीं। सिध्या के पिता माधवराव सिध्या पहले जनसंघ में फिर कांग्रेस में रहे। खुद ज्योतिरादित्य सिध्या ने राजनीति में अहला कदम कांग्रेस के माध्यम से रखा और 20 साल तक कनग्रेस में मान-सम्पान धारने के बाद अपनाम मिलते ही कांग्रेस से किनारा कार भाजपा की सदस्यता ले ली। सिध्या को मर्मिंडल में शामिल करने के पीछे उनका गजरात से रिश्ता होने के साथ ही उनकी कई समस्याओं के समाधान की काई राह नहीं दिख रही है। इन्हीं में से एक है प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जहां किसी न किसी प्रतियोगी या नियमित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सुखियों में न रहता हो। प्रश्नपत्र लीक होने की निरंतर घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता को कमजोर करती हैं और छात्रों के लिए काफी तनाव का कारण बनती हैं। इसमें मुहे को सुलझाने के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, पौद्योगिकी का लाभ उठाना, सख्त कानूनी उपाय और प्रभावित छात्रों के लिए व्यापक समर्थन शामिल है। इन उपायों को लागू करके, हम परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल कर सकते हैं और सभी छात्रों के लिए एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।

जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का टचपॉर्ट शामिल होते हैं, जहां सुरक्षा से सम्बंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: 2020 में, मैनुअल हैंडलिंग गलती के कारण बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के दैरान एक महत्वपूर्ण गलती हुई। संगठित अपाध में संलिप्तता से आपाधिक गिरोह परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का लाभ बढ़ाव देती है। उदाहरण के लिए: एडब्लूॱॉक प्रोब्लूॱॉक का उपयोग करके यह सुनिश्चित करता है कि प्रश्नपत्र सुरक्षित रूप से चिक्का हुआ हो और अवैध राजस्व अर्जित हुआ। तकनीकी कमजोरियाँ बताती हैं कि खराब सुरक्षा वाले डिजिटल सिस्टम को हैक किया जा सकता है, जिससे लीक होने का जोखिम काफी कम हो जाता है। सख्त कानूनी ढांचा लीक में शामिल व्यक्तियों और अंगों के लिए कठोर दंड लागू कर सकता है। उदाहरण के लिए: मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र हैं कि ए गए ईमेल पोर्ट के माध्यम से लीक हो गए, जिससे व्यापक वितरण हुआ। परीक्षा अधिकारी या कर्मचारी कभी-कभी वित्तीय लाभ के लिए पेपर प्रस्ताव करता है। परीक्षा कर्मचारियों सुविधाओं का उपयोग करना जरूरी है। उदाहरण के लिए: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने डेटाबेस डिजिटल संसाधनों का उपयोग शुरू किया है, जो केवल परीक्षा परिणामों पर अधिकृत कर्मियों के लिए आसान है। सुरक्षित प्रश्नपत्र प्रबंधन और वितरण के लिए ब्लॉकचेन पौद्योगिकी का उपयोग करना काफी देशव्यापी कारोबार बनाता जा रहा है, जिसके कई लाभार्थी और अंशधारक हैं। राजनेता से लेकर अधिकारी तक, प्रश्नपत्र निर्माता से लेकर समन्वयक तक, परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं और आयोगों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक की संदिग्ध भूमिका या मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रश्नपत्र लीक की लगातार घटनाएं भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई हैं। उदाहरण के लिए, अकेले प्रश्नपत्र लीक के 70 से अधिक मामले 2023 में समाझे आए, जिससे छात्रों में तनाव और चिंता को काफी हट तक बढ़ा देती है, जिससे उनका मानसिक कल्पना और परीक्षा प्रदर्शन प्रभावित होता है। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत की है, उन्हें लग सकता है कि उनकी उपलब्धियों को कम आंका गया है, जिससे शिक्षा प्रणाली और उनकी अपनी क्षमता में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। पेपर लीक की बार-बार होने वाली घटनाएं छात्रों को हक कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने भविष्य की संभावनाओं और योग्यता-आधारित सफलता के मूल्य के बारे में मोहब्बंग होने लगता है। बिहार में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के कई लीक के बाद, कई छात्र निराश महसूस करने लगे और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता में विश्वास खो दिया। छात्रों की शैक्षणिक योजनाएं परीक्षा में बैठने की आवश्यकता से बाधित होती हैं, जिससे अतिरिक्त तनाव और ताकिंक प्रतिभा पैदा होती है। प्रश्न-पत्र लीक होने से कैपड़ी विश्वास करने के लिए हेल्पलाइन और परामर्शी केंद्र स्थापित करना। भविष्य में लीक को रोकने के लिए गए प्रयासों के बारे में संगोष्ठीत संचार बनाए रखें। छात्रों और उपभोक्ताओं को विश्वास को फिर से बनाने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों और मुक्त योजनाओं के बारे में सूचित करना।

वैकल्पिक परीक्षा कार्यक्रम से बीमारियों को कम करने के लिए: मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षाओं को जल्दी से दोबारा करवाना बहुत फायदेमंद है। छात्रों के लिए लंबे समय तक तनाव से बचने के लिए स्थानीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक लीक के बाद, कई छात्र निराश महसूस करने लगे और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता में विश्वास खो दिया। छात्रों की विश्वास की आवश्यकता को कमजोर करती है और छात्रों के लिए काफी तनाव का कारण बनती है। चूंकि प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या अनियंत्रित होती जा रही है, इसलिए केंद्र समेत विभिन्न

जयंती का विशेष महात्मा गांधी का जन्मदिन भी उत्तराखण्ड के लोगों का जयंती है। यहाँ के लोगों के बीच इसका अपेक्षित रूप एवं विवरण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वामोदर वास मोदी जी ने बहुत सांच-विचार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय के साथ ही प्रवृत्तर के विकास की जिम्मेदारी दी है। सिंधिया एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र एवं समाज बनने-बनाने का हमारा चिंता पैदा कर दी है, जिससे उनकी तैयारी और आत्मविश्वास का स्तर बाधित हुआ है। प्रश्नपत्र लीक होने में मैनूअल हैंडलिंग और सुरक्षा चुक्र प्रमुख कारण है। प्रश्नपत्रों की छापाई करने का विशेष लक्षण यह है कि वे लोक करने के लिए बाहरी पक्ष के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए: 2023 में राज्य भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल होने के लिए कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए आज हमें उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल की महती आवश्यकता है। भौतिक उपयोगकर्ताओं के लिए छेड़छाड़-प्रतिक्रिया करने का लक्षण यह है कि वे लोक करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और सख्त जावाबदी भी एक उपाय हो सकता है। उदाहरण के लिए: खरों का पता लगाना और उन्हें रोकने के लिए नियमित ऑडिट करना और निगरानी प्रणाली लाग करना। प्रश्नपत्र लीक का छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर पड़ता है। इससे छात्रों में तनाव और चिंता में वृद्धि होती है। प्रश्नपत्र लीक होने से राज्यों की सरकारों का यह प्रथम एवं सर्वोच्च दायित्व होना चाहिए कि वे प्रश्नपत्र लीक होने के प्रकरणों की प्रश्नावृत्ति न होने वें और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की कोई गुंजाइश ही न रहे।

नहाराज आई दिवाली पर नदां का गतिविधि

राकेश अचल

केंद्रीय हिन्दू मत्रिमंडल में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने के पीछे क्या बजह थे जानने में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। भाजपा के इन दो हंसों की जोड़ी 2018 के विधान सभा चुनाव में आमने-सामने थी। तब महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और चौहान मप्र के मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में नेता शिवराज का नारा दिया था और कांग्रेस की ओर से माफ करो शिवराज, हमारे नेता महाराज का नारा उछला और कामयाब भी हुआ था। शिवराज सत्ताच्युत हो गए थे, लेकिन महाराज अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। मप्र की इस जोड़ी ने ही 2020 में फिर कमाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ को पदच्युत कराकर अपने अपमान का बदला लिया और एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार बनवा दी थी। 2020 से ही ये जोड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नजरों में छढ़ी हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस जोड़ी ने हाङडोड़ मेहनत कर मप्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनवाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो 2020 के करतब के लिए पुरस्कार के रूप में राज्य सभा की सदस्या और केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान मिल गया था, किन्तु शिवराज सिंह को कोई इनाम-इकराम नहीं मिला था। उलटे उनके स्थान पर मोहन यादव को अपमानित जरूर किया गया था भाजपा की ओर से। शिवराज सिंह मंजे हुए खिलाड़ी निकले। उन्होंने अपमान का कड़वा घैंट बिना ना-नुक्र के पी लिया। नरीजा ये हुआ कि 2024 के आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चौहान को भी केंद्रीय मत्रिमंडल सिंधिया को तो 2020 के करतब के लिए पुरस्कार के रूप में राज्य सभा की सदस्या और केंद्रीय मंत्री मंडल में जगह मिल गयी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो भी बनना ही था क्योंकि वे प्रधानमंत्री के गांव-गौड़े के नाते दामाद लगते हैं, लेकिन शिवराज सिंह को कोई इनाम-इकराम नहीं मिला था। मौन साधारा की बजह से मत्रिमंडल में नाम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी सुखिखों में आया, लेकिन वे शायद अभी इस लायक नहीं बन पाए हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र में बैशाखी सरकार का गठन करने के फैरन बाद, अपने मत्रिमंडल में सिंधिया और चौहान को एक खास मकसद से जगह दी है। इन दोनों को मत्रिमंडल में लिए जाने से जातीय संतुलन बना या नहीं ये भी हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि मोदी जी के पूर्व मत्रिमंडल के नाकाम कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बजह से मोदी जी और उनकी पार्टी फजीहत झेलना पड़ी उसे देखते हुए ही शिवराज सिंह चौहान को नया कृषि मंत्री बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्यप्रदेश से ही थे। वे किसान आंदोलन को ढांग से हैंडिल नहीं कर पाए थे। दरअसल तोमर यानि ग्वालियर के मुना भैया, मौन सिंह साबित हुए थे। वे न किसानों को मना पाए और न किसान युनियनों को। उन्हें किसान संगठनों से संवाद स्थापित करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। उलटे सरकार के माथे पर 700 किसानों की हत्या का दाग और

महाराज आर शिवराज पर भैरव का मतलब

केंद्रीय हिन्दू संघिसंघल में मध्यांग

नाम आने के बाद कांग्रेस ने उह्ये पार्टी से भी निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और एक निर्दलीय के रूप में लोकसभा चुनाव जितने के बाद वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे चाहते तो भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया।

मौजूदा सरकार को पूर्वोत्तर में जड़े जमाने के लिए एक उत्ताहीलाल की जरूरत थी। इस कस्टी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खरे उतरे इसीलिए उन्हें संचार मंत्रालय के साथ पूर्वोत्तर मामलों की भी जिम्मेदारी दी गयी। पूर्वोत्तर में मणिपुर सबसे ज्वलत मुद्दा है। मणिपुर के मामले में संघ और भाजपा ही नहीं खुद मोदी जी का काम साबित हुए हैं। मणिपुर अभी भी जल रहा है। संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने ने भी फिर एक बार मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने के पीछे अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद क्या वजह थे जानने में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। भाजपा के इन दो हस्तों की जोड़ी 2018 के विधान सभा चुनाव में आमने-सामने थी। तब महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और चौहान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में और कामयाब भी हुआ था। शिवराज और पूर्व केंद्रीय मंत्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने के पीछे अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद क्या वजह थे जानने में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। भाजपा के इन दो हस्तों की जोड़ी 2018 के विधान सभा चुनाव में आमने-सामने थी। तब महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो 2020 के करतब के लिए पुरस्कार के रूप में राज्य सभा की सदस्यता और केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान मिल गया था, किन्तु शिवराज सिंह को कोई इनाम-इकराम नहीं मिला था। उलटे उनके स्थान पर मोहन यादव के कडवा धूंट बिना ना-नुकर के पीलिया। नतीजा ये हुआ कि 2024 के आप चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौहान को एक खास मकसद से जगह में जगह मिल गयी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मंत्री बनना ही था योकि वे प्रधानमंत्री के गांव-गौड़े के नाते दामद लगते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उनकी योग्यता और मौन साधना की बजह से मंत्रिमंडल में नंद्रे सिंह तोमर भी मैध्यरेश से ही थे। वे किसान आंदोलन को ढंग से हैंडिल नहीं कर पाए थे। दरअसल तोमर यानि ग्वालियर के मुना भैया, मौन सिंह साबित हुए थे। वे न किसानों को मना पाए और न किसान यूनियनों को। उन्हें किसान संगठनों से संवाद स्थापित करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। उलटे सरकार के माझे पर 700 किसानों की हत्या का दाग और

बॉर्डर-2 के साथ लौट रहे सनी देओल

कहा - 27 साल पुराने गदे को पूरा करने आ रहा है

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर-2 फिल्म बॉर्डर का सीक्रियल अने वाला है। एक्टर और मेकर्स ने सोशल

मीडिया पर एक बीडियो के जरिए इसकी घोषणा की। सनी देओल की गद 2 के बाद से उनकी बॉर्डर 2 की चर्चा जोरों पर थी। गुरुवार को, फिल्म मेकर्स ने एक सेशल

बीडियो शेयर किया। बीडियो में केवल टेक्स्ट है, इसमें फिल्म से जुड़ा कोई विषय नहीं है।

और बैकग्राउंड में सनी देओल की आवाज सुनाई देती है। बीडियो में सनी कहते हैं, 27 साल पहले,

एक फैजी ने बादा किया था कि वह बापस आएगा। उसी बाद को पूरा करने, हिंदुस्तान की मिल्डो को अपना सलाम कहने, आ रहा है फिर से...

बीडियो के आखिर में फिल्म का गाना संदेशो आते हैं सुनाई देता है, जिसे सोन निगम ने गाया था। 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर में सुनीत शेंझौ, जैकी शॉफ, अमर खन्ना, सुरेश बरोनी और पुरीत जैसे कलाकारों ने काम किया था। इनके अलावा, कुलभूषण खरबदा, तब्बा, राखी, पुजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी जैसे सहायक कलाकार भी थे। फिल्म में लागेला की लड़ाई को काल्पनिक तरीके से दिखाया गया था। फिल्म में अनु मलिक ने व्यक्तिक दिया था और जावेद अख्तर ने गाने लिखे थे। यह फिल्म भारत की वाँ फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर रही।

खबर है कि 1997 में बॉर्डर को डायरेक्ट करने वाले जे.पी.दता बॉर्डर-2 को प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ उनकी बेटी नियो दता, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार को प्रोड्यूसर होंगे। इसका निर्देश अनुग्रह सिंह करेंगे। फिल्म में सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी के रोल में ही दिखाई देंगे। वहाँ आयुष्मान खुराना भी लौड रोल में नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी इन सभी खबरों की पुष्टि नहीं है।

राजनीति की तुलना में अभिनय आसान...

कंगना रणौत ने एक सफल अभिनय करियर के बाद अब राजनीति का रुख किया है और हाल ही में हिंदुचल प्रदेश के मंडी निवाचन क्षेत्र से आम चुनाव जीता है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना ने हाल ही में बताया कि कैसे उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर के बाद उनसे राजनीति में शामिल होने के लिए संर्वर्क किया गया था और कैसे वह एक सांसद के रूप में कर्तव्यों के साथ फिल्मों में अपने काम को संतुलित करने की योजना बना रही है। एक हालिया इंटरव्यू में कंगना ने खुलासा किया कि उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों से पहले स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा संपर्क किया गया है। अभिनेत्री के अनुसार, यह पहली बार नहीं है कि जब मुझसे राजनीति में शामिल होने के लिए संर्वर्क किया गया, मुझे पहले भी कई अन्य प्रस्ताव मिले हैं। गैंगस्टर के तुरंत बाद, मुझे टिकट की पेशकश की गई। मेरे परदादा कम से कम तीन बार विधायक रहे।



असल जिंदगी में मैं मिर्जापुर के गुड़ पांडित से बहुत अलग हूं: अली फजल

बैबी सीरीज मिर्जापुर के सीजन 3 का हर कोई बेस्टी से इंतजार कर रहा है। इस बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने बताया है कि उन्होंने अपने किरदार गुड़ पांडित को पहले एनालिटिकल तरीके से समझने की कोशिश की। यह उनके असल जिंदगी से बहुत अलग है। मिर्जापुर 3 में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिक दुग्ल, विजय बर्मा, हर्षिता गौर, अंजुम शर्मा, प्रियांशु पेनयुरा और ईशा तलवार जैसे कई कलाकार नजर आएंगे।

शो में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अली ने कहा, मुझे लगता है कि यह फॉर्मेट मेरी लाइफ और परफॉर्मेंस का अद्भुत हस्ताना बन गया है, क्योंकि यह एक ऐसी जाह है जहाँ लोग पूरी जीवन को छेद करते हैं, जिन्होंने सीजन 1, सीजन 2 देखा है, वह सीजन 3 की कहानी को असानी से समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि सीजन 3 में क्या है, लेकिन मैंने इसमें एक ऐसे लड़के के ग्राफ को जस्टिफाई किया है, जो अपने आस-पास इन्हें भ्रष्टाचार के बावजूद अपनी मासूमियत को बनाए रखता है। उन्होंने अगे

कहा, सीरीज की कहानी में एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मैं जुड़ हुआ नहीं हूं, लेकिन मैंने इसे एनालिटिकल तरीके से समझने की कोशिश की है। मैंने उनके लिखने के तरीके, उनके सोचने के तरीके और उन क्षेत्रों में लोगों के साथ उनके बातचार को लेन-स्टडी की। औंटू ने निश्चित रूप से उन्हें किसी भी अंदाज में बताया जा सकता है।

अली के कहा कि गुड़ पांडित बॉलीवुडर है और इस किरदार के साथ पालापन से जुड़ हुआ है। चुनौतियों के बारे में बात करते हुए अली ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को असल जिंदगी में इस किरदार से दूर रखने और कैरेक्टर को बिन जज किए निपाहने की थी। दस-एफिसोड की मिर्जापुर 3 का प्रीमियम 5 जुलाई से प्राइम वीडियो पर होगा। मिर्जापुर का असानी से प्राइम वीडियो पर होगा। मिर्जापुर का आसानी से समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि सीजन 3 में क्या है, लेकिन मैंने इसमें एक ऐसे लड़के के ग्राफ को जस्टिफाई किया है, जो अपने आस-पास इन्हें भ्रष्टाचार के बावजूद अपनी मासूमियत को बनाए रखता है। उन्होंने अगे



अन्तर्राष्ट्रीय शो द टुनाइट शो का हिस्सा होंगे दिलजीत दोसांझ, हासिल किया एक और मुकाम

कुछ समय पूर्व इन्स्टियाज अली की फिल्म चमकीला में अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले पंजाबी सिंगर और हिन्दी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता दिलजीत दोसांझ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मरोज़न दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार दिलजीत दोसांझ जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आने वाले हैं, जिसमें उनकी पांचूलियां सातवें आसमान पर जाने वाली हैं। दिलजीत दोसांझ 2018 में जारी किया गया था। दिलजीत दोसांझ 2020 में जारी किया गया था। दिलजीत दोसांझ अपनी आगामी पंजाबी फिल्म 'जट्ट एंड जूलियट 3' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वह नीरू बाजवा के साथ मुख्य भूमिका में होंगा। यह फिल्म लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रीय पहचान में जबरदस्त बढ़ावी होगी। दिलजीत दोसांझ जल्द ही अपनी आगामी पंजाबी फिल्म 'जट्ट एंड जूलियट 3' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की तीसरी कहानी है और इसका निर्वाचन जगदीप सिंह ने किया है।

फिल्म 28 जून, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

दिलजीत दोसांझ में जुड़ हुआ है कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' में अपने दिलजार अभिनय से सभी का दिल जीता। इस फिल्म में उनके किरदार को साथ देखने की तोहफा है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत दोसांझ ने जाहीर किया कि उनकी की फिल्म 'चमकीला' की बोली दिलजीत दोसांझ की जीत है।

दिलजीत

